

संपादकीय

सफल रिश्तों का सफल सम्मेलन

दिवारी में संपत्र जी-20 शिखर वार्ता की सफलता से भारत ने खुब बाहवाही पाई। वही सम्मेलन की समाप्ति के बाद राजकीय यात्रा पर भारत आए सऊदी क्राउन प्रिंस की



उपस्थिति में तमाम समझौते इस सम्मेलन के एक बोनस की तरह हैं। सऊदी अरब के साथ भारत के शिखर सदाबहार रहे हैं। लैकिन निवेश व अन्य मोर्चों पर साझेदारी ने रिश्तों को और गहराई दी है। गवर्नर में हाल के वर्ष में प्रिंस मोहम्मद बिं बिलामान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो निकटता बढ़ी है, उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी नजर आया है। हाल के दिनों में अमेरिका से सऊदी अरब के शिखों में खटास जगाहिर है। जी-20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व प्रिंस सलमान के मिले हाथों को थामे प्रधानमंत्री के हाथों वाला चिप्र अंतर्राष्ट्रीय राजनय में चर्चा का विषय रहा। बहरहाल, भारत और सऊदी अरब के बीच हुई द्विषक्षीय वार्ता के ठोस परिणाम समाप्त हैं। हाल के दिनों में जहां भारत से सऊदी अरब को नियंत्रण दिया, वहीं आयत में भी खासी वृद्धि हुई। ऐसे दोनों जब कोरोना संकट व रुस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था हिंकारे खा रही है। इससे पहले भी जब 2019 में प्रिंस सलमान भारत आए थे तो उन्होंने भी अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की थी। अब इस दिनों में साझा टारक फोर्स बनाने की घोषणा दिली वार्ता में हुई है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी खाड़ी देशों से बेहतर सरबंध बनाने को अपनी प्राथमिकता देते रहे हैं। वे पिछले कुछ वर्षों में दो बार सऊदी अरब का दौरा भी कर चुके हैं। निःसंदेह, मध्यूर्त में एक बड़ी ताकत होने के कारण सऊदी अरब से बेहतर रिश्तों के खास मायने हैं। कहीं न कठी इत्तमागिक देशों पर खासी प्रभाव वाले सऊदी अरब को भारत पक्क पर दबाव बनाने वाले सहयोगी के रूप में भी देखता है। जिसके जरिये पाक के निरंकुश बाहवाह पर नकेल करी जा सके।

हाल के वर्षों में भारत-सऊदी अरब के बीच सालाना व्यापार का पांच हजार करोड़ डॉलर का तरह पहुंचना दोनों देशों के बीच बेहतर होने रिश्तों की बानी है। कई इच्छाएँ भारतीय कंपनियों ने पिछले दिनों सऊदी अरब में दो सो करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। वही सऊदी अरब की कंपनियों दो साल पहले तक तीन सो करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत में कर चुकी थी। दरअसल, प्रिंस सलमान सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में आमूल-वूल परिवर्तन करके उस टैग को हटाना चाहते हैं कि वह सिर्फ तेल से लेने वाली अर्थव्यवस्था है। तभी वे उत्पादन, पर्यावरण, तकनीकी आदि के क्षेत्र में बड़े निवेश को आमंत्रित करते हुए भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। भारत भी सऊदी अरब के प्रधानमंत्री को एक भी प्रधानमंत्री के रूप में निवेश करने के साथ-साथ अपने आपको भारत के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बढ़ना का उद्देश करता है तो निवेशकों के लिए एक भरोसा पैदा होता है। वही दूसरी और भारतीय प्रतिभाओं व तकनीशियों से भी सऊदी अरब को खासी उमीद है। जिसके जरिये वह अपने 2030 के लिए उत्पादन की यथार्थ में बढ़ाव सके। जिसके उसकी महत्वाकांक्षी 'इको-सिटी' बासाए जाने की योजना भी शामिल है। यही वहां कि गोलबद्दल क्युनियों की दिस्त्रिब्युटी बनाने को आतुर सऊदी अरब भारत जैसे देशों से संबंध जमजूब कर रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में सऊदी अरब के सहयोग से बनने वाला महत्वाकांक्षी 'वेरेट कोर्ट रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट' दोनों देशों के बेहतर होने संबंधों की बानी है। दूसरी ओर जी-20 सम्मेलन में जी-20 प्रधानमंत्री ने 'हिंदी-मिडिल ईर्ष-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' की घोषणा की तो इसमें सऊदी अरब की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। इस प्रोजेक्ट की चीन के 'बेल एंड रोड परियोजना' के जवाब के रूप में देशों जो रहा है। बहरहाल, प्रिंस सलमान की वह टिप्पणी सुखद अहसास करती है कि जिसके उन्होंने देशों के बीच हुए हालिया समझौते संबंधों को नये आयाम दें।

जनतंत्र की अनिवार्य शर्त स्वतंत्र अभिव्यक्ति

हाल ही में संपत्र हुए जी-20 आयोजन की शानदार सफलता के बाद में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह बात अपने अप में कम महत्वपूर्ण नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक भी यह बात समर्पक कर रहे हैं कि कुछ सदस्य देशों के विरोध के बावजूद इस सम्मेलन में एक 'सर्वसम्मत' सामूहिक विवित जारी की जा सकती। भारत से लेकर अमेरिका तक वाक के मुद्दा हो या रूस-यूक्रेन का मुद्दा या फिर अफ्रीकी यूरियन को जी-20 का सदस्य बनाने का मामला, इन सबको भारत की दृष्टि की जी-20 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में ही पिणा जायेगा। जहां तक इस प्रधानमंत्री का सवाल है, निश्चित रूप से यह भव्य और शानदार था। मज़बूत में ही सही, पर कहा जा रहा है कि जी-20 के आगामी मेजबाजों के बीच जो निकटता बढ़ी है, उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी नजर आया है। हाल के दिनों में अमेरिका से सऊदी अरब के शिखों में खटास जगाहिर है। जी-20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व प्रिंस सलमान के मिले हाथों को थामे प्रधानमंत्री के हाथों वाला चिप्र अंतर्राष्ट्रीय राजनय में चर्चा का विषय रहा। बहरहाल, भारत और सऊदी अरब के बीच हुई द्विषक्षीय वार्ता के ठोस वरिणाम समाप्त हैं। हाल के दिनों में जहां भारत से सऊदी अरब को नियंत्रण दिया जायेगा तो यह आयत में भी खासी वृद्धि हुई। ऐसे दोनों बार में जब कोरोना संकट व रुस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था हिंकारे खा रही है। इससे पहले भी जब 2019 में प्रिंस सलमान भारत आए थे तो उन्होंने भी अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की थी। अब इस दिनों में साझा टारक फोर्स बनाने की घोषणा दिली वार्ता में हुई है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी मेजबाजों से 'मिलने' आये थे। उमेरीद की जा रही थी कि वे संभवतः मीडिया को संबोधित करेंगे, पर वह हाथ लिलाते हुए 'सबको धन्यवाद' कह कर जी-20 सम्मेलन के मेजबाजून राष्ट्र भरत में पेसा कुछ द्वारा नहीं दिया। भारत-अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता के बाद मोदी को बहुत उमेरीद थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से मीडिया को संबोधित करेंगे- फिर चाहे यह सबोधन प्रधानमंत्री प्रेस के सवाल-जवाब से करता है, यह बात जग-जाहिर है। भारता सरकार के दो कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। इन लगभग जी-20 सालों में प्रधानमंत्री का एक भी प्रेस-सम्मेलन में भाग न लेना चर्चा का ही नहीं, आलोचना का विषय भी बना हुआ है। और यह भी सही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसलिए अमेरिका के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बढ़ना का उद्देश करता है तो निवेशकों के लिए एक भरोसा करने के साथ अपने प्रत्यक्षकारों को सबोधन करने का अवसर नहीं नहीं दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता के अनुसार 'राष्ट्रपति बाइडेन ऐसी प्रेस-वार्ता के लिए तैयार थे, पर मेजबाजून राष्ट्र की असहमति के कारण ऐसा हो नहीं पाया।' अपने मीडिया से गाष्ट्रपति बाइडेन ने बात तो

सम्मेलन को कवर करने के लिए आये हुए थे। सबके पास पूछने के लिए कुछ था।

खासकर दुनिया के इन्हें बड़े-बड़े नेताओं के बीच जो इन्होंने जी-20 सम्मेलन के दौरान

की, पर भारत में नहीं, इंडोनेशिया में। वहां पहुंचकर उन्होंने यह कहा जी-20 सम्मेलन के दौरान

की घोषणा की, पर भारत में नहीं, इंडोनेशिया में। वहां

भारत दोनों जनतात्रिक देश हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के संदर्भ में प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के संदर्भ में एक बार जूरू आये थे प्रधानमंत्री प्रत्रकारों के समक्ष, पर तब उनसे पूछे गये सवालों के संबंधानों में इसका रूप था। यह कहा गया है कि जी-20 सम्मेलन के दौरान

भारत दोनों जनतात्रिक देशों के बीच जो इन्होंने प्रत्रकारों के संदर्भ में एक बार जूरू आये थे। यह कहा गया है कि जी-20 सम्मेलन के दौरान

भारत दोनों जनतात्रिक देशों के बीच जो इन्होंने प्रत्रकारों के संदर्भ में एक बार जूरू आये थे। यह कहा गया है कि जी-20 सम्मेलन के दौरान

भारत दोनों जनतात्रिक देशों के बीच जो इन्होंने प्रत्रकारों के संदर्भ में एक बार जूरू आये थे। यह कहा गया है कि जी-20 सम्मेलन के दौरान

भारत दोनों जनतात्रिक देशों के बीच जो इन्होंने प्रत्रकारों के संदर्भ में एक बार जूरू आये थे। यह कहा गया है कि जी-20 सम्मेलन के दौरान

भारत दोनों जनतात्रिक देशों के बीच जो इन्होंने प्रत्रकारों के संदर्भ में एक बार जूरू आये थे। यह कहा गया है कि जी-20 सम्मेलन के दौरान

भारत दोनों जनतात्रिक देशों के बीच जो इन्होंने प्रत्रकारों के संदर्भ में एक बार जूरू आये थे। यह कहा गया है कि जी-20 सम्मेलन के दौरान

भारत दोनों जनतात्रिक देशों के बीच जो इन्होंने प्रत्रकारों के संदर्भ में एक बार जूरू आये थे। यह कहा गया है कि जी-20 सम्मेलन के दौरान

भारत दोनों जनतात्रिक देशों के बीच जो इन्होंने प्रत्रकारों के संदर्भ में एक बार जूरू आये थे। यह कहा गया है कि जी-20 सम्मेलन के दौरान

भारत दोनों जनतात्रिक देशों के बीच जो इन्होंने प्रत्रकारों के संदर्भ में एक बार जूरू आये थे। यह कहा गया है कि जी-20 सम्मेलन के दौरान

